एक नजर में

पंचायत समिति नाहन में सर्वसम्मति से चयन

नाहन : सिरमौर जिला में पंचायत समिति नाहन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। भाजपा समर्थित रमेश चौधरी अध्यक्ष और माया देवी उपाध्यक्ष बनीं। बीडीओ कार्यालय नाहन में आयोजित निर्वाचन बैठक में 15 सदस्यों की पंचायत समिति में से भाजपा समर्थित 11 सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस समर्थित कोई सदस्य बैठक में नहीं आया। (जासं)

पच्छाद की राजगढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस नहीं बना सकी उपाध्यक्ष

नाहन/राजगढ़ : पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की राजगढ़ नगर पंचायत में सात वार्डों में से पांच पार्षद कांग्रेस समर्थित होने के बावजूद पार्टी उपाध्यक्ष नहीं बना सकी। कांग्रेस समर्थित विक्रम जैलदार को अध्यक्ष तथा भाजपा समर्थित नरेंद्र ठाकुर को निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए किसी पार्षद ने नामांकन नहीं किया। आंतरिक राजनीति के कारण कांग्रेस उपाध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार नहीं दे पाई। (जटी)

राजस्थान विस अध्यक्ष ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट करते राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी • सौ लोकभवन

शिमला : राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने वासुदेव देवनानी को हिमाचली शाल एवं टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज भी उपस्थित थे। (जसंके)

क्लासीफाइड

सूचना

I, Yog Raj (41 Yrs) S/o Sh. Hem Raj R/o Village Sarog, P.O. Rajain, Teh. Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) declare that my name wrongly entered in my daughter Anshika Sharma's educational record as Yograj. Whereas my correct name is Yog Raj. All Concerned note please.

I, Sareshna Devi (48Yrs.) W/o Sh. Baljeet Singh, R/o VPO Bhadiara, Teh. & Distt. Kangra (H.P.) declare that I want to change my son's name from Netan Choudhary to Nitin Choudhary. All Concerned note please.

चिकित्सा

शादी से पहले या शादी के बाद
स्त्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है आज ही इलाज करा लेना
मिले या फोन पर परामर्श ले
Dr. Hashmi
स्थापित 1926 hashmi.com
हाशमी दवाखाना अलवर-UP
8272800800
8899787114

नाम परिवर्तन

I Barfee Devi widow of Lt. No.-6447870 Rank dvr Ram Singh Regt. ASC R/O Vill. Samohli P.O Drahal teh. Jogindernagar Distt. Mandi HP have amended her name from Barfee to Barfee Devi. As my name be recorded as Barfee Devi in my husband's service record.

मैं आर्मी नं. 2477172P रैंक Ex NK (TS) जगदीश वृत्ति 14 पंजाब रेजिमेंट पुत्र चेत राम, गांव व डा.पथियूं तह.सदर जिला मंडी हि.प्र.घोषणा करता हूँ कि मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री का नाम गलती से नितिका कटोच दर्ज है, उसका सही नाम नितिका है।

I, Sandeep Kumar S/o Sanju Ram Thakur, R/o Ward No.-03, V Bandian, Khopa, (1018), Kangra, H.P.-176128, have changed my name to Sandeep Thakur.

मैं तुलसी देवी पत्नी प्यारे राम डा. खोलानाल खाहरी (553) महोगी जिला मंडी हि.प्र घोषणा करती हूं कि मैंने अपने पुत्र के आधार कार्ड रिकार्ड में उसका नाम चीरंजी लाल से बदलकर चिरंजी लाल कर लिया है।

जंगल की आग...

गर्मी बढ़ने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में वनों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। कई स्थानों पर जंगल जल रहे हैं। बुधवार रात हमीरपुर व बिलासपुर की सीमा पर जंगल में लगी आग। बुधवार को हमीरपुर और बिलासपुर की सीमा के अलावा ऊना के चिंतपूर्णी क्षेत्र में दो स्थानों पर, चंबा के डलहौजी और कांगड़ा के धर्मशाला के जंगल में आग लगी, जिससे नुकसान हुआ है • जागरण

सरकार ने 20 और स्कूल किए बंद, 73 मर्ज

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : राज्य सरकार ने शून्य पंजीकरण वाले 20 स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा पांच व इससे कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 73 स्कूलों को नजदीक के स्कूलों के साथ मर्ज किया है। सरकार की मंजूरी के बाद सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

- शून्य पंजीकरण वाले स्कूल बंद और पांच से कम विद्यार्थियों वाले किए मर्ज
- सरकार की मंजूरी के बाद सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने अधिसूचना की जारी

अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 18 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और दो सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे पाए गए जिनमें विद्यार्थियों का नामांकन शून्य था। इन विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से डी-नोटिफाई कर दिया है। इनमें बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के स्कूल शामिल हैं। सबसे अधिक 10 स्कूल शिमला जिले में बंद किए गए हैं, जबकि मंडी के छह और अन्य जिलों के चार स्कूल इस सूची में शामिल हैं। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पांच या उससे कम है, उन्हें निकटवर्ती स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया है। इस श्रेणी में 66 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और आठ सरकारी माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सबसे अधिक 20 स्कूल मंडी जिले से हैं, जबकि शिमला के 15, किन्नौर के छह, बिलासपुर व कांगड़ा के पांच-पांच तथा अन्य जिलों के स्कूलों को भी विलय सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि बंद और विलय किए स्कूलों के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों, भवनों, फर्नीचर, अभिलेखों तथा अन्य सरकारी संपत्ति के स्थानांतरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।

सरकार ने तीन वर्ष में 1350 स्कूल किए बंद व मर्ज

सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। तीन वर्ष में सरकार 1350 स्कूलों को बंद व मर्ज कर चुकी है। इन स्कूलों में जो शिक्षक तैनात हैं उन्हें ऐसे स्कूलों में तैनात किया जाएगा जहां लंबे समय से पद खाली है।

विरोध के बाद तीन कालेजों के विलय का फैसला वापस

सरकार ने लोगों के विरोध के बाद तीन कालेजों के विलय का निर्णय वापस ले लिया है। दो जून को सरकार ने कालेजों को मर्ज किया था।

लोग इसका विरोध कर रहे थे। बुधवार को विभाग ने आंशिक संशोधन करते हुए तीन सरकारी डिग्री कालेजों के विलय संबंधी आदेश वापस ले लिए। इनमें राजकीय डिग्री कालेज कुकुमसेरी (लाहुल स्पीति), राजकीय डिग्री कालेज रोहनाट (सिरमौर) और राजकीय डिग्री कालेज जयनगर (सोलन) शामिल है। अब ये तीनों कालेज पहले की तरह संचालित होते रहेंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी अधिसूचना लागू कर दी गई है।

हिमाचल के अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश, फोटोग्राफी और शूटिंग महंगी

55 वर्ष बाद शुल्क दरों में संशोधन विदेशी पर्यटकों से दोगुना शुल्क

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश, पर्यटन, फोटोग्राफी, फिल्म शूटिंग, शोध गतिविधियों व ड्रोन संचालन महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने 55 वर्ष बाद शुल्क दरों में व्यापक संशोधन किया है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। पहले सभी शुल्क 10 व 20 रुपये तक ही निर्धारित थे। विदेशी नागरिकों के लिए सभी शुल्क दोगुना होंगे।

अधिसूचना के अनुसार भारतीय नागरिकों को अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश के लिए पहले तीन दिन तक 300 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा। अधिक ठहरने पर 500 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा।

स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का आधा भुगतान करना होगा, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को शुल्क से छूट रहेगी। ड्रोन के लिए अनुमति लेनी होगी। हल्के वाहनों के प्रवेश पर 1,000 रुपये तथा भारी वाहनों पर 2,000 रुपये प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है।

शोध और अध्ययन पर भी बढ़ा शुल्क : वन्यजीव अनुसंधान, वैज्ञानिक अध्ययन और शोध गतिविधियों के लिए भारतीय नागरिकों से 100 रुपये प्रतिदिन तथा विदेशी नागरिकों से 500 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा। वार्षिक लाइसेंस शुल्क भारतीय छात्रों के लिए 500 रुपये से शुरू होकर विभिन्न श्रेणियों में 75,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

स्कूली विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क का आधा भुगतान करना होगा, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को शुल्क से छूट मिलेगी

प्रमुख बढ़ोतरी एक नजर में

रिटल कैमरा फोटोग्राफी : 625 रुपये (पहले तीन दिन), बाद में 125 रुपये प्रतिदिन।

सिने कैमरा : 12,500 से 18,500 रुपये प्रतिदिन।

फीचर फिल्म शूटिंग (निजी) : 10,000 रुपये प्रतिदिन या 60,000 रुपये प्रति सप्ताह।

फीचर फिल्म शूटिंग (सरकारी) : 6,000 रुपये प्रतिदिन या 35,000 रुपये प्रति सप्ताह।

डाक्यूमेंट्री फिल्म (निजी) : 6,000 रुपये प्रतिदिन या 30,000 रुपये प्रति सप्ताह।

डाक्यूमेंट्री फिल्म (सरकारी) : 4,000 रुपये प्रतिदिन या 20,000 रुपये प्रति सप्ताह।

होम वीडियो शूटिंग : 2,000 रुपये प्रतिदिन या 10,000 रुपये प्रति सप्ताह।

ड्रोन के लिए अनुमति जरूरी

ड्रोन कैमरों के उपयोग के लिए शुल्क निर्धारित किया है। ड्रोन संचालन के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। शैक्षणिक, अनुसंधान और जन-जागरूकता उद्देश्यों के लिए केवल भारतीय नागरिकों एवं संस्थानों को विशेष अनुमति दी जाएगी।

सरकारी एजेंसियां : पहले तीन दिन 10,000 रुपये, बाद में 15,000 रुपये प्रतिदिन।

अन्य सरकारी संस्थान : 30,000 रुपये प्रतिदिन, अतिरिक्त दिनों के लिए 45,000 रुपये प्रतिदिन।

निजी एजेंसियां, मीडिया संस्थान व एनजीओ : पहले तीन दिन 50,000 रुपये, बाद में 75,000 रुपये प्रतिदिन।

वन्यजीव व्यापार से जुड़े लाइसेंस भी हुए महंगे

सरकार ने वन्यजीव उत्पादों के निर्माण एवं व्यापार से जुड़े लाइसेंस शुल्क में भी संशोधन किया गया है। पशु उत्पादों के निर्माण अथवा व्यापार के लाइसेंस के लिए 2,500 रुपये तथा टैक्सीडर्मिस्ट के लाइसेंस के लिए 12,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

मंत्रियों और अधिकारियों का वेतन स्थगन आदेश वापस, अधिसूचना जारी

शिमला: मुख्य सचिव केके पंत द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने बुधवार को मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिवों का वेतन स्थगन का निर्णय वापस ले लिया है। अब यह स्थगन केवल मुख्यमंत्री तक सीमित रहेगा। यह निर्णय छह जून को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया था कि वेतन स्थगन की अधिसूचना केवल उनके लिए लागू होगी और अन्य के लिए इसे वापस लिया जाएगा। स्थगित वेतन का बकाया जुलाई के पूर्ण वेतन के साथ जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय वेतन स्थगन की घोषणा की थी, जिसमें अप्रैल से मुख्यमंत्री का 50 प्रतिशत, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30 प्रतिशत तथा विधायकों का 20 प्रतिशत स्थगित किया गया था। स्थगन केवल दो महीने (अप्रैल और मई) के लिए लागू रहा।

हिमफेड दो पेट्रोल पंप और नए वाणिज्यिक परिसर करेगा स्थापित

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (हिमफेड) ने प्रदेश में अपने व्यावसायिक विस्तार और आय सृजन को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में 104 एजेंडा विषयों पर चर्चा हुई। इसमें 103 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें दो नए पेट्रोल पंपों की स्थापना, फर्नीचर निर्माण इकाई, फ्लोर मिल, नए वाणिज्यिक परिसर तथा डाल्बी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना प्रमुख हैं। एक एजेंडा को विचार-विमर्श के लिए अगली बैठक तक स्थगित रखा। इन परियोजनाओं से न केवल हिमफेड की आय बढ़ेगी बल्कि किसानों, बागवानों और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।

बैठक में हिमफेड को अधिक आत्मनिर्भर, आधुनिक और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। निदेशक मंडल ने रौहड़ू, नेरवा, गुम्मा, कुनिहार और सुल्तानपुर (चंबा) में नए गोदाम-सह-वाणिज्यिक परिसरों की स्थापना को मंजूरी दी। महेश्वर सिंह चौहान ने कहा कि हिमफेड को प्रदेश की अग्रणी सहकारी संस्था के रूप में विकसित करने के लिए नई व्यावसायिक संभावनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासनिक, वित्तीय और विकासात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई।

नीरज और अजय ने करवाया डोप टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : आरोप-प्रत्यारोप के बीच पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती और एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित निजी लैब में डोप टेस्ट करवाया। देर सायं दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों के सैंपल जांच में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की मौजूदगी नहीं पाई गई।

चंडीगढ़ में बुधवार को डोप टेस्ट के बाद नीरज भारती व अजय • इंटरनेट मीडिया

नीरज भारती ने सरकार और संगठन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने भी मीडिया में पक्ष रखा था। इसके बाद नीरज ने अजय को डोप टेस्ट करवाने की चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार कर उन्होंने टेस्ट करवाया।

अजय ने कहा कि उन्हें टेस्ट की प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सुबह कांगड़ा बिना कुछ खाए चंडीगढ़ आए। नीरज भारती ने भी यहां पर डोप टेस्ट करवाया। अजय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी शराब का सेवन नहीं किया और अन्य मादक पदार्थों का प्रश्न ही नहीं उठता। नीरज ने डोप टेस्ट करवाने की बात कही थी, जिसे मैंने स्वीकार किया। यदि उनके शरीर में शराब या किसी भी नशे की एक बूंद भी पाई जाती है, तो वह किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। यदि उनके किसी भी कार्य में भ्रष्टाचार साबित होता है, तो वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं।

नीरज भारती ने कहा कि अजय बड़े भाई हैं। हमारा कोई विवाद नहीं था। जहां तक बैठकर बात करने की बात है, वह कोशिश पहले की गई थी। जो मुद्दे मैंने उठाए उनका जवाब देने के बजाय जब निजी हमले शुरू हो जाते हैं, तो फिर कई चीजें बोलनी पड़ती हैं। किसी भी टेस्ट को करवाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते यह टेस्ट हिमाचल के बाहर करवाया जाए।

डाक्टरों ने कहा था इसमें कुछ नहीं आएगा: वर्मा

अजय वर्मा ने कहा कि मैं स्वयं को साबित करने आया था। यह निजी लैब थी। डाक्टर ने पहले कह दिया था कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस टेस्ट में छह घंटे पहले तक किए नशे की रिपोर्ट ही आती है। ऐसे टेस्ट के मायने नहीं है। कोई नशा करता है या नहीं पता लगाना मुश्किल। मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूं। डाक्टरों ने कहा कि नरकोटिक्स टेस्ट में ऐसी चीजें आती है। मुझे पहले पता होता तो मैं नरकोटिक्स टेस्ट की बात करता। नीरज भारती का सबको पता है और वो स्वयं भी कहते हैं कि पहले नशा करते थे।

नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 11 जून को प्रस्तावित नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ मुख्य सचिव केके पंत, प्रधान सचिव देवेश कुमार और सचिव राकेश कंवर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री आरडीजी को बंद करने सहित हिमाचल से जुड़े अन्य मामलों की पैरवी करेंगे। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से उदार वित्तीय मदद की गुहार भी लगाएंगे, ताकि आरडीजी बंद होने से बिगड़े हिमाचल के वित्तीय संतुलन को ठीक किया जा सके। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री 12 जून तक दिल्ली में रहेंगे।

गगल हवाई अड्डा : 113 परिवारों को 16.76 करोड़ रुपये स्वीकृत

जागरण संवाद केंद्र, शिमला : प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांगड़ा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है।

सुखविन्द्र सुक्खू • जागरण अर्काइव

इस प्रक्रिया में, 113 परिवारों को 16.76 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने सरकारी भूमि पर दुकानें और अन्य व्यवसाय शुरू किए थे।

उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश में पहला मामला है, जहां सरकारी भूमि पर कारोबार करने वालों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि कांगड़ा जिला के दौरे के दौरान कई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इन दुकानदारों को सहायता राशि देने का अनुरोध किया था, जो गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

कांग्रेस के जिला व ब्लाक अध्यक्षों के कामकाज की होगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि अब कोई भी पद स्थायी नहीं रहेगा। पार्टी हर पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा करने जा रही है, जिसकी शुरुआत ब्लाक और जिला कांग्रेस कमेटियों से की जाएगी। इस महीने 17 या 18 जून को पहली समीक्षा बैठक की जा सकती है। कांग्रेस ने जिला और ब्लाक अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीनों में किए कार्यों का रिकार्ड तैयार करें। इस अवधि में किस पदाधिकारी ने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया, कितने नए पदाधिकारी जोड़े और राष्ट्रीय स्तर द्वारा जारी कार्यक्रमों को अपने जिला व ब्लाक स्तर पर आयोजित करने में उनकी भूमिका क्या रही। बैठक में इन सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इस रिपोर्ट को पार्टी हाईकमान को भी भेजा जाएगा।

- इस महीने 17 या 18 जून को हो सकती है पहली समीक्षा बैठक
- जिला व ब्लाक अध्यक्षों को कार्यों का रिकार्ड तैयार करने को कहा

हाईकमान की नजर ब्लाक, जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हर पदाधिकारी की परफरमेंस पर है। जो पदाधिकारी बेहतर कार्य करेगा, उसे संगठन में उच्च पद मिलेगा और वह चुनाव में टिकट का दावेदार भी होगा। यह बदलाव संगठन सृजन अभियान के तहत पहली बार किया जा रहा है। पार्टी की परफरमेंस का आकलन करने के लिए ग्रीन, यलो और रेड जोन बनाए हैं। ग्रीन जोन में वे पदाधिकारी होंगे जिनका कार्य सबसे बेहतर होगा, जबकि यलो जोन में औसत प्रदर्शन करने वाले नेता आएंगे, जिन्हें सुधार के लिए प्रेरित किया जाएगा। रेड जोन में वे नेता होंगे जिनकी परफरमेंस कमजोर होगी।

इस श्रेणी में आने वाले नेताओं को चेतावनी दी जाएगी और यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें पदमुक्त भी किया जा सकता है। वहीं अभी तक राज्य कार्यकारिणी में तैनाती नहीं हुई है। कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव तो बना लिए हैं, लेकिन सचिव और प्रवक्ता के पदों पर तैनाती अभी होनी है।

इन विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी का है ज्यादा ध्यान

कांग्रेस पार्टी का ध्यान उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी है जहां वह लगातार चुनाव हार रही है। इन क्षेत्रों में संगठन सृजन अभियान को मजबूती से लागू किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल एप भी विकसित की है, जिसमें हाईकमान के कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की भूमिका को अपलोड किया जाएगा।

> कांग्रेस के जिला व ब्लाक अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा बैठक इसी महीने होगी। 17 या 18 जून को बैठक हो सकती है, जल्द ही तिथि तय कर दी जाएगी।
>
> – **विनोद जिंटा,** महासचिव (संगठन) प्रदेश कांग्रेस कमेटी।

शाह की मौजूदगी में सुलझेंगे पंजाब हरियाणा और हिमाचल के मुद्दे

राज्य ब्यूरो, जागरण। उत्तर भारत के राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों और लंबित मामलों के निपटारे के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुलझने की उम्मीद है। आगामी 24 जून को शिमला में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है।

अमित शाह • जागरण अर्काइव

इसमें अमित शाह की अध्यक्षता में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर के मुख्यमंत्री और लद्दाख के उपराज्यपाल व वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। हिमाचल बैठक में पंजाब और हरियाणा के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल को मिलने वाले हिस्से के एवज में पंजाब और हरियाणा द्वारा 4,200 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने का गंभीर विषय उठाया जाएगा। देवभूमि इस बैठक में अपनी इस बकाया राशि को वसूलने के लिए पुरजोर पैरवी करेगी।

- शिमला में 24 जून को राजेगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मंच
- बीबीएमबी से मिलने वाले हिस्से का मामला उठाएगा हिमाचल
- जल विवाद के साथ अंतरराज्यीय सीमा विवादों पर होगी चर्चा

इस बैठक के केंद्र में इस बार मुख्य रूप से 'जल विवाद' और राज्यों के आपसी सीमा विवाद रहने वाले हैं। इसी दिन सचिव स्तर की स्थायी समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सभी राज्यों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से सतलुज विवाद गरमाया हुआ है।

इस बार की बैठक में जल से जुड़े मुद्दे सबसे बड़े एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। पंजाब सरकार इस बैठक में अपने जल संबंधी दावों और अधिकारों को लेकर विशेष रणनीति के साथ उतर सकती है। पंजाब का रुख साफ है कि वह अपने पानी से जुड़े मामलों को पूरी प्रमुखता से उठाएगा। पानी के साथ-साथ उत्तर भारत के राज्यों के बीच जारी अंतरराज्यीय सीमा विवाद भी मुख्य एजेंडे में शामिल हैं। पिछली बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित हुई थी।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला:- प्रथम तल, डोगरा कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स (संजेता हाईट्स), समीप सेब मंडी, भट्टाकुफर, संजौली, शिमला, हिप्र.-171006

ई-नीलामी बिक्री सूचना

विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु यह स्कैन करें

अनुलग्नक-ई

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

[अचल हेतु नियम 6(2) एवं 8(6) के साथ अनुलग्नक-II ए]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणी, मोर्टगेजर एवं गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को हाईपोथिकेटेड/मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का बैंक ऑफ बड़ौदा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी निम्न वर्णित खातों में देय राशि, किसी पहचाने गए देय राशि को देयता, जो क्रेता पर होगी, परंतु ब्रैकर पर नहीं होगी, की वसूली हेतु "जैसा है, जहां है, जो है जैसा है तथा जहां है जैसा के आधार" पर बिक्री की जाएगी। ऋणी/मोर्टगेजर/गारंटर,सिक्योर्ड परिसंपत्तियों/देय/आरक्षित कीमत/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	शाखा का नाम और ऋणी/गारंटर एवं मोर्टगेजर का नाम एवं पता	ज्ञात भार, यदि कोई हो, के साथ अचल संपत्ति का विवरण	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (संरचनात्मक/भौतिक)	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	कुल्लू शाखा:- ऋणी:-(1) मेसर्स दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोप. दीपक कुमार पुत्र श्री जवाहरलाल, गारसा रोड, पीथी भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, (2) दीपक कुमार पुत्र श्री जवाहरलाल, गारसा रोड, पीथी भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। गारंटर:-श्री सुमित वैद्य पुत्र श्री कमल किशोर, 232, गांव हाटन, पीथी बालाजुए, तहसील भुंतर, कुल्लू, हिप्र.	दीपक कुमार के नाम में दर्ज कोठी खोखान तहसील भुंतर, जिला कुल्लू हिप्र. की वर्ष 2006-07 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट खसरा सं. 1473/1242/1138, खाता खतौनी सं. 280/457 में सम्मिलित भूमि माप 1-13-0 बीघा के 9/66 हिस्से के तौर पर भूमि माप 0-4-10 बीघा पर संपत्ति के सभी भाग एवं पार्सल।	07.06.2026 तक रु. 19,22,717.59 + उपार्जित आगामी ब्याज एवं प्रभार।	15.07.2026 को अप. 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे	Rs. 17,59,500/- / Rs. 1,75,950/- / Rs. 50,000/-	बैंक का प्रतीकात्मक कब्जा	10.06.2026 से 14.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (केवल पूर्व अनुमति के साथ)

सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं सम्पर्क संख्या: श्री सुशील शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, मो. 62832-85131

ईएमडी प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि: 15.07.2026 को सायं 04.00 बजे तक

ई-नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समय: 15.07.2026 को अप. 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे ईएमडी • भुगतान की विधि एनईएफटी

बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तें हेतु, कृपया वेबसाईट लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm, https://Baanknet.com पर पधारें।

यह सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना के तौर पर भी समझी जाए

दिनांक:10.06.2026 स्थान: कुल्लू (हिप्र) प्राधिकृत अधिकारी